वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में, ऐसे 14 और केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं । इनमें दिल्ली, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं । इसके अतिरिक्त नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार हेतु दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में तीन निर्व्यसन केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

मादक द्रव्यों के व्यसनियों के संबंध में सर्वेक्षण

2824. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सभी राज्यों में और खासतौर से दिल्ली में मादक द्रव्यों और खासतौर से स्मैक के व्यसनियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण करने का विचार रखती है ताकि मादक द्रव्यों के व्यसनियों की और खासतौर से स्मैक के व्यसनियों की संख्या का पता लगाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्य रूप दिये जाने का प्रस्ताव है और उसका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) कोई व्यापक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है । फिर भी विश्वास किया जाता है कि कुछ भागों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है ।

(ख) सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या पर काबू पाने के लए अनेक उपाय किए हैं । कल्याण मंत्रालय द्वारा चेतना निर्माण, निवारक शिक्षा, परामर्श एवं मार्गदर्शन, संदर्भ सेवाएं, निर्व्यसन, अनुवर्ती कार्यवाही और व्यसनियों के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम शुरु करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है । नशीली दवाओं के विरुद्ध सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है । सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) चार महानगरों तथा पांच अन्य नगरों में 'छात्रों में नशीली दवाओं पर एक बहु-केन्द्रित अध्ययन' शुरु किया गया था । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से अपने राज्यों में स्थिति का मूल्यांकन करने तथा समस्या पर जहां कहीं विद्यमान है, काबू पाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

Workcharged Staff of C.P.W.D.

2825. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2314 given in the Rajya Sabha on the Wth August, 1987 and state:

(a) whether it is a fact that tem porary posts for workcharged staff of CPWD were sanctioned after 1st April, 1977; and

(b) if so, what are the dates of such sanction and the sanctioned posts according to each category in different regions and circles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is enclosed. *[See* Appendix CXLIV Annexure No. 125]

Arbitration regarding re-classification|re-categorisation of CPWD Workers

2826. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of